दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

मू.वि.या. सं. 233/2007

सुरक्षित: 04 फरवरी, 2014
निर्णय: 10 फरवरी, 2014

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुशील दत्त सलवान, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता के साथ
श्री प्रताप सिंह, अधिवक्ता

बनाम

मैसर्स नव निर्माण कंस्ट्रक्शन कं. ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमित चौधरी के साथ श्री संदीप शर्मा, अधिवक्तागण

कोरम: न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर

<u>निर्णय</u>

10.02.2014

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ('जी.एन.सी.टी.डी') द्वारा अपने कार्यकारी अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा यह एक याचिका है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित 19 जनवरी 2007 के पंचाट को अपास्त कर दिया जाए।

2. वर्तमान याचिका की पृष्ठभूमि यह है कि प्रतिवादी मेसर्स नव निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी ('एन.एन.सी.सी') को 9 नवंबर 1992 के पत्र द्वारा डीडीए तूफान जल के प्रवेश/निकास संरचना के निर्माण का काम सौंपा गया था। इसके बाद, पक्षकारों के बीच 18 नवंबर 1992 को एक समझौता हुआ। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच 18 नवंबर 1992 को एक समझौता किया गया। इस कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि 15 मई 1993 थी। हालाँकि, 1 सितंबर 1993 को याचिकाकर्ता द्वारा अनुबंध को रद्द कर दिया गया था और एक अन्य ठेकेदार द्वारा काम पूरा किया गया था।

3. एन.एन.सी.सी. ने समझौते के खंड 25 के अनुसार पक्षकारों के बीच विवादों का निपटान करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए 1993 में वाद संख्या 2483 दायर किया। उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित 1 मार्च 1999 के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के मुख्य अभियंता ने श्री ए.एस. गहलावत, मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया, जिन्होंने 7 जुलाई 1999 को संदर्भ दर्ज किया। एन.एन.सी.सी. ने अपने दावों का विवरण दाखिल किया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने बचाव के साथ-साथ प्रतिदावों ('सीसी') का विवरण दाखिल किया।

4. 12 मई 2000 के एक पंचाट द्वारा, विद्वान मध्यस्थ ने एन.एन.सी.सी. के दावों की अनुमति दी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिदावे को खारिज कर दिया। 2000 के मू.वि.या.संख्या 218 के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर पंचाट पर आपत्ति को न्यायालय ने 31 जुलाई 2002 को स्वीकार कर लिया था। 12 मई 2000 के पंचाट को अपास्त करते हुए, न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ को दावों और प्रतिदावों का नए सिरे से निपटान करने का निर्देश दिया।

5. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, विद्वान मध्यस्थ ने फिर से संदर्भ में प्रवेश किया, आगे की कार्यवाही की और 16 सितंबर 2002 को एक नया पंचाट पारित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मू.वि.या सं. 416 /2002 दाखिल करके पंचाट पर आपत्ति जताई। 18 जनवरी 2005 को, इस न्यायालय ने उक्त याचिका में एक आदेश पारित किया, जिसमें इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसमें विद्वान मध्यस्थ को कार्यवाही फिर से शुरू करने और 16 सितंबर 2002 के पंचाट में वापस किए गए निष्कर्षों के कारण देने का निर्देश दिया गया।

6. तीसरी बार, विद्वान मध्यस्थ ने कई मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की और 19 जनवरी 2007 का विवादित पंचाट पारित किया।

7. आग्रह किए गए पहले आधारों में से एक यह है कि 18 जनवरी 2005 के अपने आदेश में न्यायालय द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के विपरीत, विद्वान मध्यस्थ ने वास्तव में एन.एन.सी.सी द्वारा किए गए विभिन्न दावों के संबंध में निष्कर्ष के लिए कारण नहीं दिए हैं और वस्तुतः अपने पहले के पंचाट को दोहराया है, जिसे न्यायालय ने 31 जुलाई 2002 को अपास्त कर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता श्री सुशील दत्त सलवान ने दावों (iii), (iv) और (v) के तहत निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें केवल यह कहा गया है कि उक्त दावों में कारणों के लिए, दावों (i) और (ii) के तहत पहले से दिए गए कारणों का संदर्भ दिया जाना चाहिए। श्री सलवान ने आगे कहा कि यदि वास्तव में उपरोक्त दावे दावे (xvii) के घटक थे, तो विद्वान मध्यस्थ द्वारा दावे (xvii) के तहत 2,00,000 रुपये की अलग से राशि फिर से देने का कोई औचित्य नहीं था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने बताया कि विद्वान मध्यस्थ ने दावा (i) और (ii) तथा दावा (iii) से (viii) के अंतर्गत स्पष्ट किया है कि वे सभी दावा (xvii) के अंतर्गत लाभ और हानि के सभी

दावों के घटक थे। श्री शर्मा ने आगे कहा कि दावा (xvii) के संबंध में दिए गए निर्णय को याचिकाकर्ता द्वारा अब दिए गए आधार पर चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए यह अस्वीकार्य है। उन्होंने ***बिजेंद्र नाथ श्रीवास्तव बनाम मयंक श्रीवास्तव (1994) 6 एससीसी 117 में जारी*** निर्णय पर भरोसा किया। श्री शर्मा ने यह समझाने की कोशिश की कि दावा (xvii) के तहत जो दिया गया था वह दावों (i) से (viii) के ऊपर था क्योंकि लाभ की हानि की अवधारणा को ***हिंद कंस्ट्रक्शन कांट्रेक्टर बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 720*** और ***मैसर्स ए. टी. बृजपाल सिंह बनाम गुजरात राज्य ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1703*** में बताए गए कानून के संदर्भ में अच्छी तरह से मान्यता दी गई थी।

9. आक्षेपित पंचाट के अवलोकन से पता चलता है कि, वास्तव में, दावे (i) से (viii) को विद्वान मध्यस्थ द्वारा दावे (xvii) का घटक माना गया है, जो लाभ की हानि के लिए 6,40,000 रुपये की राशि के लिए है। पंचाट के शुरूआती पैराग्राफ में दावे (xvii) के संबंध में कहा गया है: "दावेदार द्वारा तैयार किए गए अलग-अलग दावों और मेरे द्वारा न्यायनिर्णय किए गए दावे सं. 1,2,3,4,5,6,7,8 के विचार में, जो आंतरिक रूप से और अनिवार्य रूप से इस दावे के घटक हैं और इस दावे के निर्णय के अतिरिक्त तदनुसार निर्णय लिए गए हैं।" 2,00,000 लाभ के हानि के लिए दावे (xvii) के तहत, दावों (i)

से (viii) के संबंध में पंचाट के अलावा, जिन्हें लाभ के हानि के दावे के घटक कहा जाता है। उस हद तक, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा दावे (xvii) के संबंध में कोई कारण नहीं दिया गया है और उस हद तक विवादित पंचाट न्यायालय द्वारा 18 जनवरी 2005 को 2002 के मू.वि.या. सं. 416 में जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप, दावे (xvii) के तहत एन.एन.सी.सी. के पक्ष में रु.2,00,000 का पंचाट को रद्द किया जाता है।

10. जहां तक दावों (i) से (viii) के संबंध में पंचाट का संबंध है, विद्वान मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि वे सभी लाभ के हानि के बड़े दावों के व्यक्तिगत घटक थे, प्रशंसनीय है। यद्यपि श्री सलवान ने दावे (vi) के तहत मूल्यह्रास के निर्णय की आलोचना की थी, जब इस तरह के दावे को लाभ के हानि के एक घटक के रूप में देखा जाता है, तो यह समझ में आता है कि इस तरह के दावे पर विचार क्यों किया गया था। इसके अलावा, जब विद्वान मध्यस्थ ने पाया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया गया था, तो दावे (i) और (ii) के तहत दिए गए कारण दावे (iii) से (viii) के तहत दिए गए पंचाट के लिए भी मान्य होंगे। परिणामस्वरूप, यह न्यायालय दावे (i) से (viii) के संबंध में आक्षेपित पंचाट में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दावों (ix) से (xi) के संबंध में पंचाट के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं है। दावे (xii), (xiii) और (xv) को अस्वीकार कर दिया गया है। दावे (xiv) के तहत बयाना राशि की वापसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुबंध की अवैध समाप्ति के बारे में विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्ष का एक तार्किक विस्तार था। इसलिए, 20,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि की वापसी को किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

12. श्री सलवान ने प्रस्तुत किया कि पंचाट स्वयं काल्पनिक दस्तावेजों पर आधारित था, जिन पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

13. न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त प्रस्तुतिकरण इस तथ्य की अनदेखी करता है कि बार-बार अवसरों के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विद्वान मध्यस्थ के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे उसके पास अभिलेख पर दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। विशेष रूप से, न्यायालय पंचाट की प्रस्तावना में निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख करना चाहेगा::

> "और जबकि, प्रत्यर्थी ने मेरे समक्ष दिनांक 4.2.2005, 26.2.2005, 11.3.2005, 23.3.2005, 8.4.2005, 4.5.2005, 24.5.2005, 6.6.2005, 20.6.2005, 8.7.2005, 22.7.2005, 3.8.2005, 14.10.2005, 5.11.2005 और 14.11.2005 की कार्यवाहियों में उनके पास प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपलब्धता, अधिवक्ता की नियुक्ति, उचित संक्षिप्तीकरण आदि के कारण मेरे समक्ष मामले को बार-बार स्थगित करने की मांग की है।"

14. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विद्वान मध्यस्थ के समक्ष मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि विद्वान मध्यस्थ काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़े। मूल अभिलेखों की अनुपस्थिति में विद्वान मध्यस्थ के पास उपरोक्त प्रस्तुतिकरण से निपटने का कोई तरीका नहीं था।

15. इसी कारण से, विद्वान मध्यस्थ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिदावों को अस्वीकार करने को भी उचित ठहराया गया था।

16. दावे (xvi) के तहत ब्याज देने के सवाल पर, यह देखा गया है कि विद्वान मध्यस्थ ने 28 अक्टूबर 1993 से भुगतान की तिथि तक दावेदार के पक्ष में 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया। ***कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड बनाम.जी. हरिश्चंद्र रेड्डी ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 817,*** और विशेष रूप, उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए कानून को ध्यान में रखते हुए

मध्यस्थता कार्यवाही के लंबे समय तक के विचाराधीनता को देखते हुए, न्यायालय उपरोक्त ब्याज दर को संशोधित करने के लिए इच्छुक है और निर्देश देता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 28 अक्टूबर 1993 से भुगतान की तिथि तक एन. एन.सी.सी. प्रतिदावे को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा जो आज से आठ सप्ताह के बाद नहीं होगा। उस अवधि के बाद भुगतान करने में कोई भी देरी देरी की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12 प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

17. परिणामस्वरूप, विद्वान मध्यस्थ का दिनांक 19 जनवरी 2007 का आक्षेपित निर्णय निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

(i) दावे (xvii) के अंतर्गत रुपए 2,00,000 का पंचाट अपास्त किया जाता है।

(ii) दावे (xvi) के तहत ब्याज के निर्धारण को संशोधित करते हुए निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एन.एन.सी.सी. को 28 अक्टूबर 1993 से भुगतान की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी, जो आज से आठ सप्ताह के बाद नहीं होगा। उस अवधि से परे भुगतान करने में किसी भी विलंब अवधि के लिए,

जी.एन.सी.टी.डी. एन.एन.सी.सी. को दी गई राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

(iii) अन्य सभी मामलों में, 19 जनवरी 2007 के आक्षेपित पंचाट को बरकरार रखा गया है।

18. याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

न्या. एस. मुरलीधर

10 फरवरी, 2014
टीपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*